केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना के तहत प्रदेश की 17 हाईवे एवं सड़क निर्माण परियोजनाओं का उदयपुर में शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर गडकरी ने उदयपुर के संदर्भ में कहा कि, उदयपुर में विकास की अपार संभावनायें हैं तथा इन परियोजनाओं से विशेषतः उदयपुर के एक्सपोर्ट उद्योग को और गति मिलेगी। गडकरी ने अपने संबोधन के दौरान जयपुर से दिल्ली के बीच इलैक्ट्रिक हाईवे बनाने की भी घोषणा की। इलैक्ट्रिक हाईवे के संदर्भ में उन्होंने कहा कि, यह देश में इस प्रकार का पहला हाईवे होगा। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी संबोधित किया।

जयपुर-दिल्ली के बीच शीघ्र बनेगा इलैक्ट्रिक हाईवे: केन्द्रीय मंत्री गडकरी

गडकरी जी से जितनी बार मिलते हैं, कार्य के साथ नये आइडिया भी मिलते है-भजन लाल शर्मा

- **केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 2500 करोड़ की 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।**
- **उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल और केवल राजनीति की है।**

उदयपुर, 12 फरवरी (कासं)। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राजस्थान में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की सौगात देते हुए ऐलान किया कि, जयपुर-दिल्ली के बीच शीघ्र इलेक्ट्रिक हाईवे बनेगा। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे के साथ ही यह इलेक्ट्रिक हाईवे एक नई लेन पर बनाया जाएगा। जयपुर से दिल्ली के बीच देश में ई-हाइवे का यह पहला प्रयोग होगा।

गडकरी सोमवार को उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के समीप एक निजी रिसॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी. जोशी सहित विभिन्न जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गडकरी ने राजस्थान में 2500 करोड़ रुपये की लागत की 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

इसके साथ ही, नितिन गडकरी ने जयपुर रिंगरोड के दूसरे चरण के लिए 5 हजार करोड़ की मंजूरी देने की घोषणा की है। रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत 92 किलोमीटर के 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का काम 3 महीने में प्रारम्भ किया जाएगा।

गडकरी ने कहा कि, उन्होंने पानी में उतरने वाले हवाई जहाज की संकल्पना की थी और साबरमती में इसे साकार किया। उन्होंने कहा कि, राजस्थान पर्यटन शहर है और यहां झीलें भी हैं। यहां भी पर्यटन की दृष्टि से पानी में भी उतर सकने वाले हवाई जहाज चलाने पर विचार किया जा सकता है, एयरपोर्ट के साथ रिवर पोर्ट पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के कहे गए वाक्य का उदाहरण देते हुए कहा कि, जहां भी रोड नेटवर्क विकसित होता है, वहां नया शहर बसता है। उन्होंने उदयपुर के नए बाईपास को लेकर कहा कि, इससे उदयपुर में एक्सपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी, जिससे उद्योगों को लाभ होगा और नए रोजगार सृजित होंगे।

गडकरी ने यह भी कहा कि, हम रोड नेटवर्क बना रहे हैं लेकिन इसके साथ हमें फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी सोचना होगा। पेट्रोल-डीज़ल से हटकर बायो फ्यूल व वैकल्पिक फ्यूल की तरफ बढ़ना होगा। उन्होंने ई-हाइवे की अवधारणा पर कहा कि, ऊपर से गुजरती इलेक्ट्रिक लाइन से तीन बसों जितनी लम्बी बस जुड़ी हुई होगी। इन बसों का सफर यात्रियों को हवाई जहाज के सफर का अहसास कराएगा। इसका किराया भी तुलनात्मक रूप से कम होगा।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री गडकरी का स्वागत करते हुए कहा कि, वे उनसे जितनी बार मिलते हैं, कार्य के साथ नए आइडिया भी मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, उदयपुर शक्ति और भक्ति की भी नगरी है। पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान में 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपने जो काम किए हैं, वे ऐतिहासिक हैं। जो भी हमने मांगा गडकरी ने दिल खोलकर दिया है। उन्होंने कहा कि, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार रोड नेटवर्क के साथ अन्य जरूरतों की दिशा में भी कार्य कर रही है।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि, हमने बजट में भी पीडब्ल्यूडी से राजस्थान को बहुत सडकें दी हैं। उन्होंने कहा कि, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया केवल और केवल राजनीति की है। दीया कुमारी ने गडकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि, आप महाराष्ट्र के नहीं राजस्थान के ही हैं, आपने राजस्थान को बहुत कुछ दिया है।

बिहार के विधानसभाध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव में हारे, पद छोड़ना पड़ा

अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में 112 तथा विपक्ष में 125 वोट पड़े

- **भाजपा ने सबसे पहले विधानसभाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश किया।**
- **आर.जे.डी. के 3 विधायकों ने भी भाजपा के पक्ष में ही विधानसभाध्यक्ष को हटाने के पक्ष में वोटिंग की।**

पटना, 12 फरवरी। बिहार विधानसभा में सोमवार को विधानसभाध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 125 के मुकाबले 112 मत से हार जाने के कारण पद से हटा दिया गया।

विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के बाद जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब सभा अध्यक्ष को हटाने के लिए भाजपा के नंदकिशोर यादव ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सभा अध्यक्ष ने नियम के तहत सदस्यों से पूछा कि, कितने सदस्य अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इस पर 38 से अधिक सदस्यों ने खड़े होकर इसका समर्थन किया। इसके बाद सभाध्यक्ष ने कहा कि, सदन में उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है इसलिए वह अब आसन खाली कर रहे हैं। सभाध्यक्ष के आसन खाली करने के बाद उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने आसन ग्रहण किया।

इसके बाद सभाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई । चर्चा के बाद मतदान कराया गया, जिसमें प्रस्ताव के समर्थन में 125 और विरोध में 112 मत पड़े। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तीन विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने सत्ता पक्ष के साथ मिलकर प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय राज्य मंत्री के बेटे मिश्रा की जमानत की मोहलत और बढ़ाई

नयी दिल्ली, 12 फरवरी । उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद कई आंदोलनकारी किसानों सहित आठ लोगों की हत्या के आरोपियों में शामिल केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत सोमवार को अगली सुनवाई तक बढ़ा दी।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले 26 सितंबर 2023 को आशीष को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने तीन अक्टूबर 2021 को हुई इस घटना के मामले में निचली अदालत से एक प्रगति रिपोर्ट लेने का निर्देश शीर्ष अदालत रजिस्ट्री को दिया। उच्चतम न्यायालय ने गत वर्ष 11 जुलाई को आशीष की अंतरिम जमानत की अवधि 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

उत्तर पूर्वी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं के एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ, उनकी मांगों को लेकर एक मीटिंग करने वाली हैं।

हरियाणा में प्रशासन ने किसान मार्च को फेल करने के लिए अंबाला, जिंद, कुरुक्षेत्र और सिरसा में कई स्थानों पर, पंजाब से लगती हुई राज्य की सीमाओं को कंकरीट के ब्लॉक्स, लोहे की कीलों और कंटीले तारों से सुरक्षित किया है।

हरियाणा सरकार ने भी सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के तहत 15 जिलों में निषेधाज्ञा लागू की है, जिसमें पांच या उससे अधिक लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ किसी भी तरह के प्रदर्शन व मार्च पर प्रतिबंध लगाया है।

पश्चिमी उत्तर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संयुक्त "रोड शो' में भी हिस्सा लेंगे। यद्यपि, यह स्पष्ट नहीं है कि अखिलेश यादव 21 फरवरी को रायबरेली में यात्रा से जुड़ेंगे या एक दिन पहले अमेठी से यात्रा में शामिल होंगे।

कांग्रेस के यात्रा में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आशा है कि यात्रा राज्य में प्रवेश करते समय, "पिछड़ा, दलित, आदिवासी" रणनीति से जुड़ेगी तथा "सामाजिक न्याय और आपसी सद्भाव के लिए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगी।

किसानों की हर गतिविधि पर ड्रोन एवं सी.सी.टी.वी. कैमरों से नज़र रखी जायेगी

दिल्ली बॉर्डर पर अर्द्ध सैनिक बलों एवं हरियाणा पुलिस की 114 कंपनियों को तैनात किया गया है

- **हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है।**
- **अंबाला से होते हुये दिल्ली-चंडीगढ़ हाइवे को बंद कर दिया गया है।**
- **किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनज़र पंजाब और दिल्ली के सभी मार्गों पर कीलें लगा दी गई हैं तथा कंटीले तारों की बाड़ लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है।**

चंडीगढ़ , 12 फरवरी। किसानों के मंगलवार के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम करने का दावा सोमवार को किया।

पुलिस के जारी बयान के अनुसार प्रदेश में 114 कंपनियों की अलग-अलग जिलों में तैनाती की गई है इनमें से 64 कंपनियां अर्ध सैनिक बलों तथा 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की शामिल है। ये सभी कंपनियां दंगा प्रतिरोधी उपकरणों के साथ प्रदेश के सीमावर्ती जिलों तथा संवेदनशील जिलों में तैनात है। इसके अलावा उपद्रवियों तथा शरारती तत्वों पर ड्रोन, सी.सी.टी.वी. कैमरे आदि के माध्यम से नजर रखी जा रही है।प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है।

इसके अलावा अंबाला होते हुए चंडीगढ़ -दिल्ली हाइवे बंद कर दिया है और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को पंचकूला, बरवाला, साहा, शाहबाद, कुरूक्षेत्र के रास्ते अथवा पंचकूला, बरवाला, यमुनानगर (एनएच-344) , लाडवा, इंद्री, करनाल होते हुए दिल्ली पहुँचने की ऐडवायजरी जारी की है।

पंजाब के साथ लगी सीमाएं सील होने के कारण पंजाब जाने वाले यात्रियों को रेल मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।

इस बीच सिरसा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के मंगलवार को 'दिल्ली कूच' को लेकर पुलिस व प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पुलिस व अद्धसैनिक बल के जवान हरियाणा पंजाब को जोडऩे वाले मार्गों पर बैरीकेट और किलें लगाकर डटे हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से किसानों की तैयारियों का पूरा खुलासा नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने सोमवार को सिरसा जिला के विभिन्न गावों में ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों व ग्रामीणों को दिल्ली जाने के लिए निमंत्रण दिया।

सिरसा से पंजाब के दूसरे जिलों व राजधानी चंडीगढ़ से आज भी सड़कों के जरिये संपर्क टूटा रहा। पुलिस अधीक्षक प्रशांत भूषण व जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सरहद पर लगाए गए नाकों को निरीक्षण किया व अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये।

पुलिस अधीक्षक प्रशात भूषण ने बताया कि, डबवाली-सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबवाली की ओर से आने वाले वाहनों का रूट डायवर्ट करते हुए गांव पन्नीवाला मोटा से भागसर, खारियां, रानियां तथा ओटू से मल्लेकां, माधोसिगाना, मोडिया खेड़ा से होकर नाथूसरी चोपटा की ओर निकाला जा रहा है ताकि वे आगे अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा पनीवाला मोटा तथा डबवाली की ओर से आने वाले वाहनों को जाने के लिए पंजुआना से शेखुपुरिया ,जोधपुरिया, धोतड़ , ओटू , मौजदीन, मल्लेकां व माधोसिंघाना से होते हुए नाथूसरी चोपटा की ओर निकाला जाएगा।

लोकसभा चुनाव नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, लेकिन, अपने पुत्र राहुल को पार्टी के नेता के रूप में स्थापित करने की उनकी इच्छा के कारण, कांग्रेस पार्टी में धीरे-धीरे भारी अव्यवस्था पैदा हो गई है और परिणाम यह हुआ है कि, अयोग्य नेता सलाहकार बनकर उभरे हैं जो रूप से दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं और इस से पुरानी पार्टी की गिरती संभावनाओं को सोनिया गाँधी से बेहतर कौन बता सकता है।

सोनिया गाँधी इस पर विचार और पुनर्विचार करें।

- **इधर एक वर्ग का यह भी कहना है कि, लोकसभा चुनाव लड़ने के निर्देश से डरे वरिष्ठ नेता सोनिया के नाम पर खुद को बचाना चाहते हैं, वे ही सोनिया के राज्यसभा जाने की खबर चला रहे हैं।**

राजनीतिक चाटूकार अधिक हैं।

यह दिलचस्प है कि चाटूकार नेताओं द्वारा एक सुनियोजित अभियान चलाया गया था उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य इकाइयों ने सोनिया गाँधी को, उनके राज्यों से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए प्रस्ताव पारित करवाना सुनिश्चित किया। सोनिया गाँधी के राजस्थान से भी राज्यसभा सदस्य बनने की चर्चा है।

कांग्रेस पार्टी का पतन अब स्पष्ट

पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने केवल रायबरेली से चुनाव जीता था। राहुल गाँधी परिवार के पुराने गढ़, अमेठी क्षेत्र से चुनाव हार गये थे।

इस बार सोनिया गाँधी अगर राज्यसभा में जाने का निर्णय लेती है तो कांग्रेस को सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश से कोई भी सीट नहीं (शून्य) मिलने की आशंका है।

यह कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील हो सकती है।

मदन राठौड़ व चुन्नीलाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया तो उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी थी। हालांकि पार्टी की मान-मनुहार के बाद वे मान गए और नाम वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि, इसी का परिणाम रहा कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि, भाजपा में वो लंबे समय से संगठन में काम रह रहे हैं। चुन्नीलाल गरासिया राजस्थान सरकार में मंत्री और संगठन में कई पदों पर रहे हैं। इसके साथ वे भाजपा एसटी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। गरासिया वर्तमान में भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।

राजस्थान से 10 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। वर्तमान में 6 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा के सांसद काबिज हैं। एक सीट खाली चल रही है। नोटिफिकेशन के अनुसार, 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल करने के अगले दिन 16 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। इसके बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। 27 फरवरी को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। फिर 27 फरवरी की शाम 5 बजे मतगणना होगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी ने भाजपा के दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ को उम्मीदवार बनाने पर शुभकामनाएं।

7 नए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जबकि, अधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल व बंसीलाल भाटी को जोधपुर स्थित हाई कोर्ट की मुख्य पीठ के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है। राज्य सरकार इससे पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता नियुक्त कर चुकी है।

अशोक चव्हाण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रमुख नेताओं मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और उल्हास पाटिल सहित कई प्रमुख नेता पार्टी छोड़कर भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए।

सूत्रों के मुताबिक, चव्हाण वर्तमान विधायकों समेत कुछ बड़े नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि, ये कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस की अंदरुनी कलह की वजह से हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, कांग्रेस की अंदरुनी कलह की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दिया है। यदि भाजपा में कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि, मैं पहले कह चुका हूं, महाराष्ट्र कि कांग्रेस पार्टी में अंदरुनी बहुत कलह है। यह कलह इतनी ज्यादा है कि देवड़ा जी चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, आज अशोक चव्हाण ने रिजाइन कर दिया।

नीतीश ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर तंज कसते हुए कहा, "आप बिहार के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि क्या वह नीतीश जी पर भरोसा करता है। मैं उन शब्दों को यहां नहीं कह सकता जो वे उनके इस्तेमाल करेंगे।" वर्ष 2013 से अब तक कुमार ने पांच बार गठबंधन बदले हैं और पांचों बार मुख्यमंत्री रहते हुए। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की "गारंटी" के आश्वासन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, "क्या मोदी जी इस बात की गारंटी लेंगे कि अब नीतीश जी पुनः गठबंधन नहीं बदलेंगे।" यादव परिवार के 34 वर्षीय वंशज ने घोषणा करते हुए कहा, "जब समय आयेगा तब तेजस्वी यहां आएगा। यह भी कहा, "हम थके हारे लोगों को नहीं चाहते परन्तु हम मजबूरियों को समझते हैं।"

शुभेन्दु और भाजपा के 5 विधायकों का विधानसभा से निलंबन

- **प. बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बंदोपाध्याय ने उन्हें शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया।**

कोलकाता, 12 फरवरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंद्योपाध्याय ने सोमवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पांच अन्य विधायकों को शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भाजपा के विधानमंडल सदस्यों ने जब सदन में प्रवेश किया तो उनकी कमीज पर लाल स्याही से लिखा हुआ था कि वे संदेशखाली के साथ हैं।

इसके बाद स्पीकर ने दंडात्मक कार्यवाही की। संदेशखाली उत्तर 24 परगना का एक क्षेत्र है जहां गांव के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। इन नेताओं में पांच जनवरी से फरार शाहजहां शेख भी शामिल है।

जब विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसी कमीज पहनने पर आपत्ति जताई, तो भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी की। अध्यक्ष द्वारा भाजपा विधायकों को निलंबित करने की घोषणा के बाद शुभेन्दुअधिकारी ने बहिर्गमन का नेतृत्व किया और निषेधाज्ञा लागू करने तथा राज्य पुलिस और 'तृणमूल के गुंडों' द्वारा संदेशखाली के ग्रामीणों पर कथित अत्याचार की निंदा करते हुए नारे लगाए।

'उपमुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का पद अन्य मंत्रियों के जैसा है।

याचिका की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने कहा कि, "यह केवल एक लेबल है। भले ही उन्हें उपमुख्यमंत्री का पदनाम दिया गया हो, वे हैं तो एक एम.एल.ए. ही हैं।" वे पद के अनुसार उच्च वेतन प्राप्त नहीं करते हैं। वे भी दूसरे सदस्यों की तरह ही है, हो सकता है उन्हें थोड़ा अधिक वरिष्ठ समझा जाता है हो अन्यों की तुलना में। यह टिप्पणी तीन न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश ने की।

याचिकाकर्ता ने बैंच में तर्क दिया जिसमें न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला व मनोज मिश्रा भी थे, ने कहा कि यहां सवाल सैलरी को लेकर नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि वो ऐसा करके अन्य सरकारी प्राधिकारियों के लिए भी गलत उदाहरण स्थापित कर रहे हैं।'

तृणमूल के खिलाफ महिलाओं....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्हें रात में बुलाते थे।

अगर वे उनकी बात नहीं मानती थीं तो उनके पतियों को पीटा जाता था। क्षेत्र की एक महिला ने स्थानीय टीवी चैनल पर स्वीकार किया कि उन्हें अपने गांव छोड़कर कलकत्ता व अन्य जगहों पर जाना पड़ा।

महिलाओं के नेतृत्व में असंतोष बढ़ता जा रहा है और आंदोलन का रुप ले रहा है। हिंसा बढ़ गई है आरोपियों के घरों व सम्पतियों को जलाया जा रहा है। इन घटनाओं के बाद राज्य पुलिस हरकत में आई और कई गांववालों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया हालांकि इनमें से अधिकांश को अदालत ने रिहा कर दिया।

क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ क्षेत्र के भाजपा नेता विक्रम सिन्हा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो अभी जेल में हैं, माकपा के एक पूर्व विधायक को भी गिरफ्तार किया।

अजीब बात है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो गृहमंत्री भी है, ने हिंसा करने वालों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए पर फरार नेताओं की गिरफ्तारी पर एक भी शब्द नहीं कहा।

गांव की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और आरोपियों के घरों में आग लगा दी। पर दोनों तृणमूल नेता शेख शाहजहां और शिबू हाजरा फरार हैं और तीसरा उत्तम सरदार पकड़ा गया है।

गुस्साई भीड़ ने शिबू के पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी और उसका घर भी जला दिया। स्थानीय दुकानदारों ने तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा हफ्ता वसूली किए जाने की शिकायत की।

राज्यपाल ए.वी. आनंदा बोस ने सोमवार को गांवों का दौरा किया और त्वरित कार्यवाही की मांग की।

विपक्ष के नेता सुभेन्द्र अधिकारी को इन गांवों का दौरा करने से रोका गया तो उन्होंने अपने लोगों के साथ सड़कों पर धरना दिया।

राज्य महिला आयोग की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया स्थानीय महिलाओं ने अपनी पीड़ा और नाराज़गी उन्हें बताई। पूरे राज्य में भाजपा और माकपा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

कतर की जेल में बंद सभी 8 पूर्व नौसैनिक रिहा हुये

इन आठ में से सात नौसैनिक भारत वापस आ गए हैं

- **इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, कतर में इन पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप मे गिरफ्तार किया गया था, तथा पिछले साल इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी।**
- **सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने इस मामले में बेहद संजीदा कदम उठाये और इन नौसैनिको की पैरवी करने में कोई कसर नहीं रखी, इसी कारण यह मुमकिन हुआ है।**

कतर, 12 फरवरी। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है, ये वही पूर्व सैनिक हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन भारत की कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया। आठ में सात पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच भी चुके हैं। कतर के इस फैसले का भारत के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है। इस मामले में भारत सरकार की कूटनीति की खूब तारीफ हो रही है।

गौरतलब है कि, कुछ दिन पहले लोकसभा में ए.आई.एम.आई.एम. चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा था कि, कतर में फंसे सैनिकों को वापस लाकर दिखाइए। किसे मालूम था कि सरकार अंदरखाने ऐसी रणनीति बनाएगी कि हमारे पूर्व नौसैनिकों को कतर वापस भेज देगा।

कतर के इस फैसले का भारत के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है। बीते तीन माह पूर्व कतर की अदालत ने इन आठ पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासो की बदौलत कुछ दिनों के बाद सैनिकों की सजा को माफ कर दिया गया। दरअसल भारत और कतर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में भारत ने शुरू से ही इस मामले को लेकर कतर से बातचीत जारी रखी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्द अल-थानी से दुबई में हुए सीओपी 28 सम्मेलन से इतर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के मसले पर बात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मीटिंग का जिक्र करते हुए ये बताया कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक अच्छी वार्ता हुई।

गौर करने की बात ये भी है कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई उस समय हुई है, जब पिछले सप्ताह ही दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। ये डील अगले 20 सालों के लिए हुई है और इसकी लागत 78 अरब डॉलर है। भारत की पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) कंपनी ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये करार किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस से भारत में बिजली, उर्वरक और सीएनजी बनाई जाएगी।

कतर में आठ भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाने की बात की पुष्टि होते ही भारत का विदेश मंत्रालय इस मसले को सुलझाने में लग गया। कतर में भारत के पूर्व राजदूत दीपक मित्तल वहां की सरकार से सजा खारिज करने के लिए चर्चा में जुट गए। कतर में भारत सरकार का पक्ष रखने में मित्तल की बड़ी भूमिका रही, वो कतर में मार्च तक भारतीय राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। एक तरफ जहां सरकार कतर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रणनीतियों को अंजाम दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर भी काम कर रही थी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908